What is the future thinking of the Government?

SHRI SIKANDAR BAKHT: The hon. Member is confusing the rehabilitation of old migrants and new migrants. This question relates to the new migrants. What he has pointed out relates to the old migrants who are already in West Bengal and the question of residual rehabilitation facilities is under consideration.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I am an East Bengal refugee settled in Andaman and Nicobar Islands. I have seen the reply given by the hon. Minister. In respect of rehabilitation in Andaman and Nicobar islands by the Rehabilitation Ministry already they have spent more than Rs. 10 crores and it may be more. They have settled only about 1200 families. I understand that originally the scheme was to rehabilitate 12,000 families. Later on it was reduced to 6,600 families. Then again it was reduced on the basis of the ecological effects as he has stated. Considering all these pros and cons, the Expert Committee recommended that only 2,500 families can be accommodated. I am fully aware of the fact that in Andaman and Nicobar islands there are many old settlers also. There is the local population which is already settled there. They are also demanding land. That is why in the original rehabilitation programme it was decided that 25 per cent of the reclaimed area should be allotted to the old settlers, those who are landless families. Already, for the Break-water Scheme at Hutbay in the Andaman and Nicobar Islands, Rs. 5 crores have been spent. The road has been laid and other things done. The Rehabilitation Ministry's RRO Unit has stationed some heavy machineries there. After spending Rs. 10 crores, if sufficient number of families are not inducted, the scheme will become futile. Already only 500 families are inducted. They could not have social facilities, medical facilities and educational facilities economically. Until and unless another 2000 families are inducted, it will not be possible to provide all these things to them economically. So, I want to know his reply on this specific question.

MR. SPEAKER: He wants that all facilities should be provided for.

SHRI SIKANDAR BAKHT: For families inducted, we provide all amenities.

MR. SPEAKER: He wants to know whether you will induct more and more families in order to provide better facilities.

SHRI SIKANDAR BAKHT: All rehabilitation facilities which have to be provided to the settlers in the Andaman and Nicobar island have already been provided for.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जन साधारण के लिए सस्ते मकान

*103. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण जन साधारण के लिये सस्ते और पर्याप्त संख्या में मकान देने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I wanted to know from the hon Minister since the last seven months after the Janata Party Government has taken over, considering the housing shortage in Delhi, whether they have stopped the entire construction programme in Delhi areas

SHRI SIKANDAR BAKHT. I have not followed his question

MR SPEAKER He wants to know whether the entire construction programme in Delhi has been stopped or has the Ministry taken up the construction programme?

SHRI SIKANDAR BAKHT No It has not been stopped At the moment some houses are under construction and I can give you the number Under the programme 1000 houses are ready for allotment and 2 810 houses are in various stages of construction

SHRI MANORANJAN BHAKTA After taking over as Minister of Housing what were the new constructions that you have undertaken?

SHRI SIKANDAR BAKHT After my induction no new constructions have been undertaken.

श्री कंवर लाल गुप्त मंत्री जी दिल्ली के हैं। उनको मालूम ही है कि दिल्ली की आबादी एक साल मे डेढ दो लाख बढती है। दुनिया मे शायद कोई कैंपिटल ऐसा नही है जिस मे इतनी तेजी से आबादी बढती हो। स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए तीस हजार टनेमेंट्स हर साल बनने चाहियें। आज प्राइवेट सैक्टर मे, डी डी ए और सब मिला कर मुश्किल से बारह तेरह हजार ही बनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 18 हजार की सालाना कमी रह जाती है और इसके अलावा बैकलाग भी है। डी डी ए आजकल कम्प्लीट मैस मे है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कौन से कदम उठाए हैं जिससे कम से कम स्टेट्स को को रखे, दिल्ली मे बैक लाग न बढे और दिल्ली के लोगों को सस्ते मकान और ठीक मकान मिल जाएं?

श्री सिकन्दर बख्त मकानात की समस्या सारे हिन्दुस्तान की बहुत गम्भीर है और साथ साथ दिल्ली की भी। यह कहना वर्क्स मिनिस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है कि बढती हुई आबादी और बैंक लाग दोनों को जितनी मकानात की डिमांड होगी वह सब पूरी हो सकेगी। लेकिन इतना मैं यकीन दिलाता हूं कि वर्क्स मिनिस्ट्री बहुत तेजी के साथ दिल्ली के अलावा पूरे देश की तस्वीर को सामने रख कर मकानात ज्यादा से ज्यादा मिलें, उसका प्रोग्राम बना रही है। मैं कह सकता हूं कि थोडे अरसे के बाद, लम्बे चौडे अर्से के बाद नही, आनरेबल मैम्बर महसूस करेंगे कि दिल्ली के लोगों को ही नही बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों की मकानात की समस्या डिसिनेबल शक्ल मे हल होगी।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: My question was. what specific steps is the Government proposing to take or is taking to change the *status quo* in Delhi—I am not at the moment concerned with the whole of India, I am only interested in Delhi—, what specific steps do Government propose to take or you have taken so far? What is the problem in Delhi? And what you are doing now?

श्री सिकन्दर बख्त स्टाट आर यू डूइंग का जवाब हो गया है और स्टेटस को मेन्टेन करने का सवाल दूसरा है। हम यह कर रहे है कि जितनी गवर्नमेंटल मशीनरी है उसके लिए फैसला यह किया गया है कि पब्लिक फंड से सिर्फ उनके लिए ही मकान बनेंगे जो 1,000 रुपए से कम के इन्कम ग्रुप मे आते हैं। उसके अलावा हम कन्स्ट्रक्शन ऐक्टिविटी डिस्पर्स कर रहे है। कोआपरेटिव सोसायटीज को ज्यादा से ज्यादा इनवाल्व करना चाहते हैं, प्राइवेट बिल्डर्स को इन्वाल्व करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डिस्पर्स हों ताकि रिसोर्सेज पर बोझ न पडे और ज्यादा से ज्यादा मकानात दे सकें। यही कहा जा सकता है।

श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी : माननीय कंवर लाल गुप्त जी ने अभी कहा कि इस दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, और दिल्ली में आसपास के इलाकों से भी काफी लोग आ गये है, तो क्या उनके मंत्रालय ने कोई ऐसा तसमीना किया है कि पाच साल मे कितने मकानो की उनको जरूरत होगी, और जो सबसे से चीपेस्ट मकान बनेगा उसकी कीमत क्या होगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह वुरुस्त है कि पिछले दिनो मे नसबन्दी का प्रोग्राम बहुत सख्ती से चलने के बावजूद भी दिल्ली की आबादी बढने से नही रुकी, और समस्या को इस मुनासबत मे देखे हमारे माननीय सदस्य कि अगर 20 साल मे हम हिन्दुस्तान मे मकानात की समस्या को हल करना चाहते है तो हमको 50 लाख मकान हर साल बनाने होंगे । उसी मुनासबत से दिल्ली की समस्या को देख लिया जाय । इसीलिए मैने कोई वाजे जवाब नही दिया है कि दिल्ली के सस्ते मकानात की समस्या दूर होगी कि नही । मैने यही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा दूर होगी ।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI I have asked whether his Ministry has made any assessment about the requirement of cheap houses over the next five yeas and also what would be the cost of these cheap houses?

SHRI SIKANDAR BAKHT : The latest position about the cost of houses is. . .

जनता हाउसेज जो होगे हमारे, इस वक्त हम इस एक्सरसाइज में लगें है कि बिल्डिंग मेटीरियल, टेकनीक आफ कस्ट्रक्शन, जो डिपार्टमेंटल चार्जेज जो डी० डी० ए० लगाता रहा है उसमें कमी करे ।

MR. SPEAKER : The question is : Have you made any assessment?

SHRI SIKANDAR BAKHT : We have not yet come to a proper assessment.

श्री निर्मल चन्द्र जैन मंत्री महोदय ने प्रश्न (क) के उत्तर मे नही मे जवाब दिया है जिसका मतलब यह होता है कि सस्ते मकान पर्याप्त सख्या मे सरकार देने में एसफल रही है । एक तो इसमें यह प्रश्न उठता है कि सस्ता मकान जो होगा वह कितने मे पडेगा । हम लोगों को जो नोटिस आये है डी० डी० ए० से हमारी 500 रु० तनख्वाह है और हमको 65,000 रुपये का मकान अलाट किये जाने की योजना है । तो सस्ते मकान का मतलब क्या होता है ? और कितनी सख्या मे यहा पर मकान बने है और कितनी कितनी इन्कम ग्रुप के हिसाब से कितनी कीस्ट के मकान बने है ।

श्री सिकन्दर बख्त पहली चीज यह है कि मकानात की कीमत बेरी करनी रही है

over the last 10 years that is, 1968 to 1977 there has been an increase in the cost of construction to the tune of two and a half times It cannot be helped because of increase in the cost of building material, etc. we have already some sort of a reduction; some sort of a reduction has already been affected. It was related to the departmental charges From 15 per cent the departmental charges had been reduced to ten per cent in the case of LIG houses and from 11 per cent to eight per cent in the case of Janata Houses

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 45 हजार प्लाटस ऐसे है जो को-आपरेटिव सोसायटीज को दे दिए गए है, लेकिन उनको पजेशन नही मिला । जो अनऑथोराइज्ड है, कालोनीज है, उनके रेगुलराइजेशन से 25,30 हजार प्लाटस और

निकल सकते है । क्योकि बिल्डिंग ऐक्विटी आप एलाऊ करेंगे तो उसमे भी 25,30 हजार प्लाट ऐसे है जिनमे 1 लाख से ज्यादा रेंस बन सकते है । जिनम न गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है और न ही किसी और को दिक्कत है । अगर उसमे डी० डी० ए० बिल्डिंग एक्टिविटी एलाऊ कर दे तो यह काम हो सकता है । क्या मत्री महोदय यह एश्योर करेंगे कि 2 3 महीने में इसका मौर्ट आउट कर के वह ऐसा करेंगे कि जिसस बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू हो जाए ताकि मिडिल क्लास और लो-इनकम वालो के लिए यह टेनामेंटस उपलब्ध हो जाये और दिल्ली मे हाउसिंग का प्रावलम कछ कम हो सके ?

श्री सिकन्दर बख्त मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि यह गवर्मेंट इस वक्त हाउस बिल्डिंग सोसायटीज को कन्स्टक्शन में ज्यादा-से-ज्यादा इन्वाल्व करने की कोशिश मे है ।

MR SPEAKER We go to the next question question No 104 We have spent forty minutes on four questions

श्री राम लाल राही अध्यक्ष महोदय मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । हम लोग पिछली सीटो पर बठे हुए है दुर्भाग्य हमारा यह है कि बार-बार खडे होने के बाद भी . . . .

MR SPEAKER That is not a point of order Question No 104

Allotment of Bungalow to Congress Souvenir Committee and Youth Congress

*104 SHRI YADVENDRA DUTT Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether the Bungalow on Raisina Road allotted to the Congress Souvenir Committee and Youth Congress has been allotted to them permanently,

(b) if so, the amount of rent being charged, and

(c) if not will the Government get it vacated?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) and (b) No Sir Bungalow No 5, was allotted to the All India Congress Committee, on payment of rent at market rate of Rs 2392/- p m since revised to Rs 3156/- p m from 1st January, 1977 The licence deed was revoked vide letter dated 12th May, 1977

(c) Eviction proceedings under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 has been started against the All India Congress Committee to get the premises vacated

SHRI YADVENDRA DUTT Is it a fact that in the past the Congress Committee had not paid the rent and if so what are the total dues from the AICC for this bungalow and when was the notice issued to them?

SHRI SIKANDAR BAKHT I am sorry I do not have the details of arrears just now

SHRI YADVENDRA DUTT You can ask for notice

SHRI SIKANDAR BAKHT Notices have been issued, I cannot give the date just now

SHRI YADVENDRA DUTT My question has not been answered Either the Minister should say I demand notice, or he should answer the question Evasive answers will not do I seek your protection You should ask the Minister to act in the proper fashion